

दैनिक खबरों की दुनिया



मोदी साथे
राजस्थान

नेता, नीति, नीयत सही, तो नतीजे भी सही...

राजस्थान के डबल इंजन सरकार के कार्य

सड़क नेटवर्क का विस्तार

- जनता की सुगम राह के लिए 1000 करोड़ रुपए की स्वीकृति
- 2 हजार करोड़ रुपए की लागत से 1 हजार किलोमीटर स्टेट हाइवे का सुदृश्यकरण

गैस सिलेंडर, पेट्रोल और डीजल की कीमतों में राहत

- उच्चला एवं अन्य गैसों की कीमतों में राहत
- माह मिलेगा एक रुपये की गैस सिलेंडर
- प्रदेश में पेट्रोल व डीजल की कीमतों को कम करने के लिए वैट में 2 प्रतिशत की कटौती

सबका होगा अच्छा स्वास्थ्य

- फ्रेंड सरकार द्वारा लागू आयुष्मान भारत-प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना एवं प्रदेश में संचालित स्वास्थ्य बीमा योजना को एकीकृत कर मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना लागू
- योजना के तहत अब केंसर और बीमारियों में डे-केयर पैकेज की सुविधा

किसान कल्याण को समर्पित सरकार

- पीएम किसान सम्मान निधि के तहत मिलने वाली राशि बढ़कर 8 हजार रुपए
- गेहूं के न्यूनतम समर्थन मूल्य 2275 रुपए पर 125 रुपए का अतिरिक्त बोनस

महिला सुरक्षा और सशक्तिकरण

- राज्य के सभी शालेय थानों में महिला डेस्क एवं प्रत्येक ज़िले में एकी योगियों स्टेटर का गठन
- प्रत्येक ज़िले में सीसीटीवी कैमरे स्थापित

प्रदेश में जल उपलब्धता का नया युग

- संशोधित पार्वती-कालीसिंध-चम्बल (एकीकृत ईआरसीपी) परियोजना से पूर्वी राजस्थान के 21 ज़िलों में 2 लाख 80 हजार हेक्टेयर नें लहलहाएंगी फसलें। प्रदेश की 40 प्रतिशत आबादी को जिलेगा पेयजल

शिक्षित राजस्थान-विकसित राजस्थान

- कक्षा 1 से 8वीं तक के सभी विद्यार्थियों तथा कक्षा 9 से 12वीं तक की छात्राओं को स्कूल बैग, किताबें तथा यूनिफॉर्म के लिए प्रति विद्यार्थी 1 हजार रुपए की सहायता

युवाओं के लिए दोजगार

- युवाओं को दोजगार देने हेतु आगामी वर्ष में होगी लगभग 70 हजार पदों पर भर्तियां
- दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल विकास योजना एवं मुख्यमंत्री कौशल विकास योजना के तहत युवक-युवतियों को निःशुल्क कौशल प्रशिक्षण

अपराध की दोकथान के लिए नए कदम

- 1046 हिस्ट्रीशीटर्स एवं हार्डकोर और इनामी अपराधियों सहित कुल 9 हजार 994 गिरफ्तार
- ब्रह्माचार पर योग के लिए राज्य में कार्यवाही हेतु सीबीआई को अनुमति की गयी ताकि खलम



मोदी की गारंटी

कमल का बटन दबाएं, भाजपा को जिताएं

अबकी बार 400 पर

अशोक चतुर्वेदी
लेखक

सुन है अमेरिका में व्यक्ति के मरने के बाद उसकी संपत्ति का आधा हिस्सा सरकार के पास चला जाता है...बाकी के बच्चे हकदार होते हैं...सैम पिट्रोदा ने एक टीवी चैनल पर बातचीत में विचार साझा किया तो हज़ार मचाओ जमात ने शब्द पकड़ लिए...अब शोर मचाए हैं...कहते हैं सामने वाले आए तो विरासत कर के नाम पर तुम्हारी संपत्ति हड्डप लेंगे...कर भी बढ़ा देंगे...आईटी सेल के मुखिया तो ऐसे हज़ार मचाए हैं...मानो सारा सब कल ही होने वाला है...बच्चों से लेकर नाती-पोते तक की चिंता कर डाली है...बता दें ये वही लोग हैं जो सार्वजनिक सभाओं में परिवारवाद की खिलाफ करते हैं...और

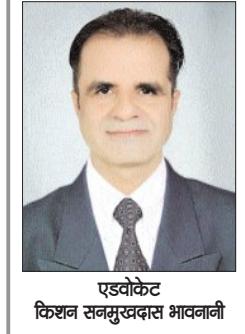
दांव लगता है तो पीढ़ियों की चिंता सतती है...अगर परिवारवाद से नफरत है तो खुश होना चाहिए...विरासत कर से परिवारवाद कमज़ोर होगा...वैसे धर्मिक ग्रंथ गीता भी यही संदेश देती है...गीता में कहा गया है कि क्या साथ लाए थे...क्या साथ ले जाओगे...जो लिया है यहीं से लिया है...यहीं छोड़ कर जाना पड़ेगा...तो सनातनी को निश्चिंत हो जाना चाहिए...खुद से विरासत कर की पैरवी करनी चाहिए...हालांकि अभी यह विचार चर्चा में भी नहीं आया है...महज सैम पिट्रोदा ने एक कार्यक्रम में इस पर बात की थी...इसी बात पर हंगामा हो गया है...दरअसल, कुछ लोगों को बात का बत्तगंड बनाने का हुनर हासिल है...ये सारे दिन इसी ताक में रहते हैं कि कोई मुद्दा हाथ लगे...सैम ने जैसे ही बात कही...इन्हें लपक लिया...अब शेर मचाए हैं कि अगर ये सत्ता में आ गए तो ऐसा कर देंगे...वैसा कर देंगे...यानि ये एक तरह से मान रहे हैं कि ये सत्ता में नहीं आ रहे...वरना तो चार सौ पार का दावा करने वालों को ऐसी बातें शेखा नहीं देती...तो ये ही होती है...सरकार चाहे तो 99 साल बाद

हिंदुस्तान में एक कानून पहले से ही है...अगर इसे अक्षरतः लागू कर दिया जाए



तो आधी तो क्या परी संपत्ति ही परिवार के हाथ से जा सकती है...अर्थात यहां मकान-दुकान-जमीन की लीज 99 साल के लिए होती है...सरकार चाहे तो 99 साल बाद

विज़न 2047 की नींव हमारी बौद्धिक, शारीरिक प्रतिभाओं को विदेशों में प्लायन से रोकने सख्त नियम बनाना जरूरी

एस्केप्ट
किशन संघरुदास भावाली

वैश्विक स्तर पर यह जग प्रसिद्ध है कि भारत मानवीय, बौद्धिक, शारीरिक प्रतिभाओं की खान है। इसके सटीक प्रमाण के रूप में हम देख सकते हैं कि यूरोपीय संघ के अनेक देशों में बड़ी-बड़ी अधिनियमों के संरीणों याद बढ़े बढ़े अधिकारी पूर्ण भारतीय हैं, इस तरह अगर हम 54 देश के अप्रोत्यायी यूनियन 53 देश के इस्लामिक सहयोग संगठन में देखें तो भारतीय प्रतिभावान श्रम हमें अधिक देखेगा। इस तरह हम अगर उच्चप्रतिभावान भारतीय डॉक्टरों इंजीनियरों को देखें तो वह भी अमेरिका जैसे विकसित देश में बहुत अधिक हैं जिसका प्रमाण मैं अपने रिसर्चरों के देख सकता हूं कि बहुत टैलेंट इंजीनियर आज अमेरिकी कंपनी में बड़ी पोस्ट पर हैं, जो पूरा परिवार अमेरिकी नागरिक बन चुका है।

इस विषय पर चर्चा आज हम इवलाइए कर रहे हैं, चूंकि दिनांक 22 अप्रैल 2024 को यूरोपीय संघ ने अपने 29 सदस्य देशों के बीच नियम बदल आसान होने की कर्तव्य याचिकाएं के लिए याचिदानंद नियमों में कुछ बदलाव किए हैं।

भारत में यूरोपीय संघ संघर्ष के बीच लोगों से लोगों के बीच संपर्क बढ़ाने की ओर कदम बढ़ाया गया है। बीजीं नियमों में यह बदलाव किए हैं। यह बदलाव के बीच लोगों से लोगों के बीच संपर्क मजबूत संबंधों को देखते हुए लिया गया है।

यह नया सिस्टम शुरू किया है। यह नया सिस्टम भारतीय नागरिकों के लिए विशेष रूप से तैयार एक अपडेट बीजीं सिस्टम शुरू किया है।

यह नया सिस्टम भारतीय नागरिकों के लिए यूरोपीय संघ ने इस बात की जानकारी दी है, यूरोपीय संघ की तरफ से जारी बयान में कहा गया है, जो भारतीय कम समय के लिए शेषों बीजीं के मानकों की तुलना में अधिक अनुकूल है। उन्हें इस नये बीजीं नियम के तहत पांच सालों के लिए बीजीं नियम के अनुकूल होने की ओर सकते हैं।

कुल मिलकर इसमें भारतीय प्रतिभावान अकर्तव्य होने और अन्य प्रायोगिक कम समय के लिए अपलाई करते हैं,

बाद, अगर हमको पासपोर्ट में सही वैलेटी बीकी है तो हमको पांच-साल की बीजीं मिल सकता है। चूंकि यूरोपीय संघ के 29 देशों के बीजीं नियम बदल के दौरान, धारकों को बाराबर ट्रेवल के नागरिकों के बाराबर ट्रेवल के अधिकार दिये जाते हैं, इसका भलतब यह है कि वे अलग-अलग बीजीं की जरूरत के बिना शेषों देशों में कई बड़ी समस्या है, जो इन लोगों को प्रशिक्षित करने में अपने संसाधनों के बावर अलग-अलग बीजीं सकते हैं। इस व्यवस्था को लागू करने का उद्देश्य यूरोपीय संघ के बीच धारकों को वैश्वीकृति बढ़ावा देना है, जिसमें 25 यूरोपीय सभा के सदस्य देशों और अन्य धारकों के बीच लोगों के प्रतिभाव के अनुसार देशों के बीच नहीं है, जिसमें 29 यूरोपीय सभा के सदस्य देशों के बीच नहीं है, जिसमें 2022 में कम से कम 65,960 भारतीय आधिकारिक तारं पर अमेरिकी नागरिक बन गए और इसी के साथ जिन देशों के लोगों को अमेरिकी नागरिकता मिली है, उनकी संख्या के मामले में भारत में अधिकारिक सदस्यों के बाद दूसरे नंबर पर आधिकारिक बन गए हैं, जो इन लोगों को जरूरत के बिना शेषों देशों में कई बड़ी बातों खर्च करते हैं, लेकिन यह बीजीं की लागू करने का उद्देश्य यूरोपीय सभा के सदस्य देशों और अन्य धारकों के बीच नहीं है, जिसमें 2022 में कम से कम 65,960 भारतीय आधिकारिक तारं पर अमेरिकी नागरिक बन गए और इसी के साथ जिन देशों के लोगों को अधिकारिक बन गए हैं, जो इन लोगों को प्रशिक्षित करने में अपने संसाधनों के बावर अलग-अलग बीजीं सकते हैं। इस व्यवस्था को लागू करने का उद्देश्य यूरोपीय सभा के सदस्य देशों और अन्य धारकों के बीच नहीं है, जिसमें 2022 में कम से कम 65,960 भारतीय आधिकारिक तारं पर अमेरिकी नागरिक बन गए और इसी के साथ जिन देशों के लोगों को अधिकारिक बन गए हैं, जो इन लोगों को प्रशिक्षित करने में कम से कम 65,960 भारतीय आधिकारिक तारं पर अमेरिकी नागरिक बन गए हैं, जो इन लोगों को जरूरत के बिना शेषों देशों में कई बड़ी बातों खर्च करते हैं, लेकिन यह बीजीं की लागू करने का उद्देश्य यूरोपीय सभा के सदस्य देशों और अन्य धारकों के बीच नहीं है, जिसमें 2022 में कम से कम 65,960 भारतीय आधिकारिक तारं पर अमेरिकी नागरिक बन गए हैं, जो इन लोगों को प्रशिक्षित करने में कम से कम 65,960 भारतीय आधिकारिक तारं पर अमेरिकी नागरिक बन गए हैं, जो इन लोगों को जरूरत के बिना शेषों देशों में कई बड़ी बातों खर्च करते हैं, लेकिन यह बीजीं की लागू करने का उद्देश्य यूरोपीय सभा के सदस्य देशों और अन्य धारकों के बीच नहीं है, जिसमें 2022 में कम से कम 65,960 भारतीय आधिकारिक तारं पर अमेरिकी नागरिक बन गए हैं, जो इन लोगों को प्रशिक्षित करने में कम से कम 65,960 भारतीय आधिकारिक तारं पर अमेरिकी नागरिक बन गए हैं, जो इन लोगों को जरूरत के बिना शेषों देशों में कई बड़ी बातों खर्च करते हैं, लेकिन यह बीजीं की लागू करने का उद्देश्य यूरोपीय सभा के सदस्य देशों और अन्य धारकों के बीच नहीं है, जिसमें 2022 में कम से कम 65,960 भारतीय आधिकारिक तारं पर अमेरिकी नागरिक बन गए हैं, जो इन लोगों को प्रशिक्षित करने में कम से कम 65,960 भारतीय आधिकारिक तारं पर अमेरिकी नागरिक बन गए हैं, जो इन लोगों को जरूरत के बिना शेषों देशों में कई बड़ी बातों खर्च करते हैं, लेकिन यह बीजीं की लागू करने का उद्देश्य यूरोपीय सभा के सदस्य देशों और अन्य धारकों के बीच नहीं है, जिसमें 2022 में कम से कम 65,960 भारतीय आधिकारिक तारं पर अमेरिकी नागरिक बन गए हैं, जो इन लोगों को प्रशिक्षित करने में कम से कम 65,960 भारतीय आधिकारिक तारं पर अमेरिकी नागरिक बन गए हैं, जो इन लोगों को जरूरत के बिना शेषों देशों में कई बड़ी बातों खर्च करते हैं, लेकिन यह बीजीं की लागू करने का उद्देश्य यूरोपीय सभा के सदस्य देशों और अन्य धारकों के बीच नहीं है, जिसमें 2022 में कम से कम 65,960 भारतीय आधिकारिक तारं पर अमेरिकी नागरिक बन गए हैं, जो इन लोगों को प्रशिक्षित करने में कम से कम 65,960 भारतीय आधिकारिक तारं पर अमेरिकी नागरिक बन गए हैं, जो इन लोगों को जरूरत के बिना शेषों देशों में कई बड़ी बातों खर्च करते हैं, लेकिन यह बीजीं की लागू करने का उद्देश्य यूरोपीय सभा के सदस्य देशों और अन्य धारकों के बीच नहीं है, जिसमें 2022 में कम से कम 65,960 भारतीय आधिकारिक तारं पर अमेरिकी नागरिक बन गए हैं, जो इन लोगों को प्रशिक्षित करने में कम से कम 65,960 भारतीय आधिकारिक तारं पर अमेरिकी नागरिक बन गए हैं, जो इन लोगों को जरूरत के बिना शेषों देशों में कई बड़ी बातों खर्च करते हैं, लेकिन यह बीजीं की लागू करने का उद्देश्य यूरोपीय सभा के सदस्य देशों और अन्य धारकों के बीच नहीं है, जिसमें 2022 में कम से कम 65,960 भारतीय आधिकारिक तारं पर अमेरिकी नागरिक बन गए हैं, जो इन लोगों को प्रशिक्षित करने में कम से कम 65,960 भारतीय आधिकारिक तारं पर अमेरिकी नागरिक बन गए हैं, जो इन लोगों को जरूरत के बिना शेषों देशों में कई बड़ी बातों खर्च करते हैं, लेकिन यह बीजीं की लागू करने का उद्द

